भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
औषध विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2134
दिनांक 12 दिसंबर, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

दवा की दुकानों पर उपभोक्ताओं का शोषण

2134. श्री संजय दिना पाटीलः
डॉ. अमोल रामसिंग कोल्हेः
श्री भास्कर मुरलीधर भगरेः
श्रीमती सुप्रिया सुलेः
श्री धैर्यशील राजसिंह मोहिते पाटीलः
प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़ः

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि महाराष्ट्र में उपभोक्ताओं के साथ दवा की दुकानों और मेडिकल स्टोरों द्वारा खुली या बिना पैकेज की गई दवाओं की बिक्री के माध्यम से उनका शोषण किया जा रहा है और इन दवाओं की कीमत उनके प्रति यूनिट अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) से काफी अधिक है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और महाराष्ट्र में मौजूदा तंत्र, जो खुली बिक्री पर टैबलेट, कैप्सूल या सिरप के मूल्य निर्धारण को नियंत्रित करता है, जब वे अपनी मूल स्ट्रिप या बोतल पैकेजिंग के बिना बेची जाती हैं, का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस पद्धति के संबंध में विशेष रूप से महाराष्ट्र में कोई अध्ययन किया है या शिकायतें प्राप्त की हैं और यदि हाँ, तो ऐसी शिकायतों या निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) महाराष्ट्र में इस शोषणकारी प्रथा को रोकने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी भी प्रकार की दवा की बिक्री के लिए उपभोक्ताओं से एम आर पी से अधिक शुल्क न लिया जाए, सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं या प्रस्तावित हैं?

उत्तर

रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (घ): राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 ("डीपीसीओ, 2013") के प्रावधानों के अनुसार औषधियों के मूल्यों की निगरानी करता है। डीपीसीओ, 2013 के तहत, किसी भी फॉर्मूलेशन के विनिर्माता को उस फॉर्मूलेशन के कंटेनर के लेबल पर अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) मुद्रित करना अनिवार्य है। इसके अलावा, किसी भी डीलर को किसी भी खुली मात्रा को फॉर्मूलेशन के आनुपातिक मूल्य से अधिक मूल्य पर बिक्री करने की अनुमति नहीं है। एनपीपीए

दवाओं के मूल्यों की निगरानी करता है और राज्यों में स्थापित मूल्य निगरानी और संसाधन इकाइयों और राज्य औषधि नियंत्रकों (महाराष्ट्र राज्य सहित), खुले बाजार से खरीदे गए नमूनों, बाजार डेटाबेस की रिपोर्टों और शिकायत निवारण चैनलों के माध्यम से दर्ज की गई शिकायतों सहित किसी भी स्रोत से अधिप्रभारन के संबंध में प्राप्त संदर्भों के आधार पर डीपीसीओ, 2013 के प्रावधानों के अनुसार उन कंपनियों के विरुद्ध कार्रवाई करता है जो उपभोक्ताओं से अधिप्रभारन कर रही हैं। एनपीपीए ने सूचित किया है कि प्रश्न में यथा उल्लिखित खुली या बिना पैकेज की गई दवाओं की बिक्री उनके प्रति यूनिट एमआरपी से अत्यधिक मूल्यों पर किए जाने के संबंध में कोई शिकायत, महाराष्ट्र राज्य सहित, एनपीपीए को प्राप्त नहीं हुई है।

*****